जवाब देही, पारदर्शिता में 'ई–शासन' (E-Governanc) क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका एवं प्रासंगिकता

*डॉ. हंसकुमार शर्मा

शोध सारांश

भारत के ई–गवर्नेस (ई–सरकार या ई–प्रशासन) की शुरूआत रक्षा सेवाओं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव तथा कर संग्रह आदि के कम्प्यूटरीकरण के साथ–साथ सन् 1970 में ही शुरू हो गई थी, मगर उस समय तक उक्त विषयों से सम्बन्धित दस्तावेजों तथा आंकडों को सिर्फ कम्प्यूटरों में सुरक्षित करने तक ही इसका प्रयोग किया जाता था। 90 के दशक में वर्ल्ड वाईड वेब तथा इन्टरनेट के आगमन के साथ ही इन आंकडों–दस्तावेजों तथा सूचनाओं का बहुपक्षीय अन्तरण, आवागमन तथा संग्रहण भी शुरू किया जाने लगा वर्ष 2000 तक बी.एस.एन. एल. तथा एम.टी.एन.एल. ने आप्टिकल फाइबर नेटवर्क तथा सेटेलाईट सेवाओं के द्वारा देश के सभी प्रमुख मंत्रालयों, विभागों, बैंकों वित्तीय संस्थानों तथा कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण करके इन्टरनेट सेवाओं से जोडना शुरू कर दिया, इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में आई.टी. अधिनियम 2000 लागू किया गया था जिसमें डिजिटल सेवाओं के सुरक्षित उपयोग तथा आवागमन से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान बनाए गए।

नागरिकों की सरकारी नीतियों में सहभागिता बढाने तथा आम आदमी तक सरकारी सेवाओं की सुगमता बढाने के लिए मई 2006 में ''राष्ट्रीय ई शासन'' योजना एन.ई.जी.पी. शुरू की गई एन.ई.जी.पी. में वर्तमान में 27^0 ''मिशन मोड परियोजना'' एम.एम.पी. तथा 8 सम्पूरक घटकों को शामिल किया गया है, जिन्हें केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सरकारों में लागू करने का निर्णय लिया गया। एन.इ.जी.पी. की शुरूआत इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौधोगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा की गई। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, तथा पासपोर्ट, राज्य स्तर पर भू–अभिलेख, कृषि तथा ई डिस्ट्रिक्ट तथा स्थानीय स्तर पर ई पंचायत मिशन मोड की शुरूआत की गई, जिससे निश्चित रूप से शासन प्रणाली (ICT) में सूचना व संचार प्रणाली के प्रयोग से सेवा लागतों में कमी आई है तथा गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

ई–गवर्नेंस परियोजना–2006

यू.पी.ए. सरकार द्वारा 18 मई 2006 को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौधौगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा 'ई शासन परियोजना' का शुभारम्भ किया गया था, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था (1) प्रशासनिक कार्यो का संचालन ई–गवर्नेस के माध्यम से करना तथा (2) सरकारी सेवाओं को लोगों को उनके क्षेत्र में ही कम लागत से कामन सर्विस डिलेवरी आऊटलेट्स के माध्यम से सुगम–पारदर्शिता के साथ विश्वसनीय ढंग से उपलब्ध कराना । वर्तमान में इसमें 27 'मिशन मोड प्रोजेक्ट तथा 8 सहायक (सम्पूरक) घटकों को शामिल किया गया है, इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर भूमि सुधार, भू–अभिलेख तथा जिला ओर स्थानीय स्तर पर पंचायतों, नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं को संचार व सूचनाओं (ITC) से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत सभी विभागों तथा उनकी कार्य योजनाओं के कम्प्यूटीकरण तथा डिजिटलीकरण पर

ध्यान दिया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत सूचना व संचार प्रौधोगिकी के सम्मिश्रण समायोजन से ऐसी व्यवस्था बनायी जा रही है जिसमें आम आदमी कहीं भी कभी भी सरकारी सेवाओं, सूचनाओं तथा सुविधाओं का डिजिटल व आन लाईन माध्यम से त्वरित लाभ उठा सकता है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रभावी तरीके से सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है।

(अ) स्टेट वाईज एरिया नेटवर्क (SWAN), (ब) सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) तथा राज्य आकडा केन्द्र (SDC) के अन्तर्गत विभिन्न मिशन मोड प्रोजेक्ट (SWAN) के तहत नागरिक केन्द्रिय सेवाओं को एक गेटवे (संयोजन) के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सी.एस.सी. राज्यों में वेबसक्षम ई–गर्वनैंस सेवाओं को प्रदान करता है, जिसमें आवेदन प्रपत्र, प्रमाण–पत्र, तथा बिजली, पानी व फोन के बिलों के भुगतान जैसी सेवाऐं शामिल है इसी प्रकार राज्य ऑकडों केन्द्रों की स्थापना सेवाओं, अनुप्रयोगों एवं संरचनाओं को राज्यों के लिए G2C, G2G and G2B सेवओं में प्रभावी इलेक्ट्रोनिक वितरण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। भविष्य में समय–समय पर मानव संसाधन मंत्रालय के तहत नेशनल सर्विस डिलवरी, इंफ्रास्ट्रेक्चर, आन लाईन UIDAI आधार, मोबाईल सर्विस डिलवरी गेटवे, नेशनल क्लाउड मिशन तथा स्टेट पोर्टल व अन्य प्रक्रियाओं को शामिल किया गया।

विशिष्ट पहचान संख्या 'आधार'

यूनिक आईडेटिंफिकेशन ऑथोरिटी आफ इण्डिया (UIDAI) ''भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान 12 अंकों वाली 'आधार योजना' का शुभारम्भ 23 अप्रेल 2010 को जारी किया गया। इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को जनसांख्यिकी तथा बायोमीट्रिक जानकारी वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या आधार कार्ड 'आधार' 29 सितम्बर 2010 को 'नंदुरबार जिले' महाराष्ट्र के 'तेम्भली' गॉव में वितरण किया गया, जिसका विभिन्न राजकीय एवं नागरिक सेवाओं की आपूर्ति, सत्यापन तथा पंजीकरण मे आधार कार्ड एक आवश्यक व अहम भूमिका निभा रहा है, ई–गवर्नैंस के क्षेत्र में इनकी उपयोगिता सम्पूर्ण समाज के कार्यो में उपयोगिता बढी हैं वर्तमान में आधार का उपयोग वैयक्तिक पहचान, प्रत्यक्ष नगद सब्सिडी अन्तरण तथा बैकिंग वित्तीय, शिक्षा, रोजगार, तमाम बहुउद्देशीय कार्यो के लिए किया जा रहा है।

ई–गवर्नैंस की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये कदमः–

1– 1 जून 2013 को पहली डीबीटीएल योजना लागू की गई 'नगद सब्सिडी देने तथा इसका लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक सीधे पहुँचाने का उद्देश्य एवं लक्ष्य हेतु।

2– 15 नवम्बर 2014 को पुनः इस योजना में संशोधित प्रारूप 1 जनवरी, 2015 से प्रारम्भ उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उसके खाते में पहुँच जाती है यदि कोई स्वतः छोडना चाहता है मार्च 2015 से 'गिव इट अप' अभियान चलाया गया। जिसके तहत 1 करोड से अधिक लोगों ने एल.पी.जी. सब्सिडी छोड दी।

3– आई.टी. से प्रत्येक नागरिक को जोडने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को 'डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की शुरूआत की गई इसके तहत इन्टरनेट कनेक्टिविटी, ई–शासन प्रौधोगिकी में सुधार, सेवाओं की इलेक्ट्रानिकी सुपुर्दगी, सभी के लिए सूचनाए व सेवाऐं तथा इलेक्ट्रानिक व हार्डवेयर सूचना प्रौधौगिकी 'इस एकल कार्यक्रम के तहत विभिन्न लक्ष्यों को शामिल किया गया।

4– 'भारत नेट योजना' शुरू की गई जिसमें सरकारी आंकडों के मुताबिक मार्च 2015 तक 20000 ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कवर किया गया था, जबकि दिसम्बर 2015 तक 32,272 ग्राम पंचायतों को कवर किया जा चुका है।

5– 'डिजिटल लाकर प्रणाली' जिसके तहत भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम करने तथा ई–दस्तावेजों की सुगमता के लिए सक्षम प्रणाली करने का उद्देश्य रहा था। इसके माध्यम से सभी दस्तावेजों को निःशुल्क डिजिटल भण्डारण किया जायेगा, भण्डारण में संकलन ई–दस्तावेजों का भण्डारण 'पहुच द्वार' एवं उपयोगकर्ताओं को यूआरआई प्यूनिफोर्म रिसोर्स डेडीकेटर' के माध्यम से ई दस्तावेज प्राप्त करने की समस्त प्रणाली मुहैया करवाना है।

6– 'राष्ट्रीय ई–शासन' (NEGP) के ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना' का मुख्य लक्ष्य 2.47 लाख पंचायतों की आन्तरिक क्रिया कलापों का स्वचालन सुनिश्चित कारक जिसमें सम्पूर्ण कार्य योजना संकलित व अवलोकित रहेगी।'

7– शासन के नागरिकों को अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माई गर्वनमेन्ट डाट इन को एक मंच के रूप में शुरू किया जिसे गया मोबाईल पर उपलब्ध कराना रहा है।

8– 28 अगस्त 2014 को शुरू प्रधानमंत्री जन–धन योजना' जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार तथा नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोडना है।

9– केन्द्र व राज्य सरकारों ने तकरीबन अपने सारे मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को कम्प्यूटरिकृत करके इण्टरनेट प्रणाली में जोड दिया जिसमें ई–कामर्स, ई–प्रोक्यूरमेंट, ई–टिक्टिंग, ई–बिलिंग, ई हास्पिटल, ई–ऐज्यूकेशन, टेलीमेडिसन, टेलीकाप्रेसिंग इत्यादि तमाम क्षेत्रों को ई–गवर्नेन्स के साथ समायोजित करके सूचना व संचार प्रौधोगिकी की तीव्र प्रसार की और अग्रसर है।

डिजिटल इण्डिया के 9 स्तम्भ

1– ब्राडबैंड हारवेज 2– फोन तक सबकी पहुँच 3– सार्वजनिक इण्टरनेट ऐक्सेस प्रोग्राम 4– ई–गवर्नेन्स (आई.टी) की मदद से सरकारी तंत्र सुधार 5– ई क्रान्ति सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी, 6–सबको सूचना 7–इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भरता, शून्य आयात 8– नौकरियों के लिए आई टी. का इस्तेमाल 9– अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम

– आप्टिकल फाईवर केबलों का संजाल बिछाकर ब्राडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार सरकार के बडे लक्ष्यों में शामिल है इसके अलावा बी.एस.एन.एल. ने 30 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए अगली पीढी के नेटवर्क (एन.जी. एन) की शुरूआत की है। यह आवाज, डेटा, मल्टीमिडिया, विडियों तथा अन्य प्रकार की सेवाओं के प्रबन्धन की एक आई.पी. (इण्टरनेट प्रोवाईडर) प्रोधौगिकी है 'वाई–फाई–स्पाट' बनाने एवं वेव पोर्टल, तथा मोबाईल एप एवं डिजिटल इण्डिया के तहत साक्षरता व प्रशिक्षण दिया गया है। ई–गवर्नेन्स के तहत 1551 पर काल करके खेती से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, मौसम व जलवायु, मंडी सुविधाऐं, बीज, खाद, आदि हांसिल का सकते है।

– ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर नीतिगत पहल की योजना, डिजिटल इण्डिया मिशन के तहत सेन्टर डवलपमेन्ट आफ एडवांय कम्प्यूटिंग की मदद से ई हस्ताक्षर (डिजिटल हस्ताक्षर) फ्रेमवर्क की शुरूआत की गई है। आधार ई (के. वाई. सी.) के जरिये ई–हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए अंगुली का निशान, ऑखों की पुतली का स्कैन कर आधार कार्ड के तहत पंजीकृत नम्बर पर ओ.टी.पी. का विकल्प अपनाया जाऐगा यह डिजिटल हस्ताक्षर कानूनी रूप से भी वैध माना जाएगा, जिससे अन्य कोई समस्या नहीं है हार्डवेयर सिक्योरिटी माडल'(एच. एस.एम.) पर एक बार उपयोग पर लाने के पश्चात् तुरन्त निरस्त कर दिया जाता है।

– आनलाईन ओ.आर.एस. के तहत ई–हास्पिटल एप्लिकेशन' शुरू सम्पूर्ण विवरण दर्ज रहेगा सरकार द्वारा 'शिक्षा

पोर्टल' 'एकल खिडकी' 'ई–पोर्टल' समय–समय पर ई–पेमेन्ट को बढावा देने के लिए अनेक प्रयास जारी है जिसमें आधार कार्ड 'भीम' (बी.एच.आई.एम.) ऐप भी जारी किया गया है।

ये सम्पूर्ण 'ई शासन' के माध्यम से सुशासन 'स्वच्छ शासन' अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था, जिसमें न भय हो, न भूख, न ही भ्रष्टाचार साधारण शब्दों में सुशासन न केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार से मुक्त शासन बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता भी होगी ओर साथ में जनता के प्रति जबाव देही भी होगा, सुशासन में जनता को सूचना का अधिकार प्राप्त होगा सुशासन वैज्ञानिक प्रशासनिक सिद्धान्तों पर आधारित जिसमें आदेश की एकता, पद सोपान, नियन्त्रण का क्षेत्र, भर्ती, प्रशिक्षण, पदौन्नति आदि की बेहतर सार्वजनिक सूचना प्रेषित रहेंगें प्रशासन में अनुशासन, मनोबल बना रहेगा और नियोक्ता–कर्मचारी सम्बन्ध वेहतर होंगें। नौकरशाही का स्वरूप आदर्श नहीं जनता के लिए काम सार्वजनिक प्रेषित रहेंगें नौकरशाही, मंत्री–सम्बन्ध सहयोगात्मक और जन कल्याणकारी होगा सुशासन में संचार की उत्तम व्यवस्था होगी तथा नेतृत्व सही व्यक्ति के हाथ में होगा। प्रशासन व योजना का सम्बन्ध विकास से जुडा होगा तथा वित्तीय प्रशासन जनहितकारी उद्देश्यों से परिपूर्ण होगा प्रशासन मे संलग्न लोग राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होंगें ये सम्पूर्ण कार्य व उद्देश्य 'ई–शासन' द्वारा ही स्थापित हो सकते है जिसमें जवाबदेही सुशासन के लिए आवश्यक है उसी प्रकार पारदर्शिता भी सरकार के कार्य, उद्देश्य, विश्लेषण, प्रगति की जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराना ही प्रशासन के पारदर्शिता है जो वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विकसित एवं विकाशसील राष्ट्रों का तुलनात्मक विश्लेषण भारत जैसे विस्तृत लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रासंगिक प्रतीत हो रही है।

***प्राचार्य**
श्री वीर तेजाजी महाविधालय,
राडावास (जयपुर)

संदर्भ सूची

1. डॉ.पी.डी. शर्मा, लोकप्रशासन सिद्धान्त व व्यवहार, कॉलेज बुक डिपो, 1995
2. अवस्थी एण्ड अवस्थीः लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2000
3. डा. अशोक कुमार : राजनीति विज्ञान, उपकार प्रकाशन, आगरा2005
4. मासिक पत्रिका योजना, सूयना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. दैनिक समाचार पत्र।